



## The Haryana General Land Security and Rent Recovery Act, 1985

Act 15 of 1985

**Keyword(s):**

**Land, Land Owner, Tenant, Rent**

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

**[हरियाणा सामान्य प्रयोजन भूमि बेदखली तथा किराया वसूली अधिनियम, 1985]**  
(1985 का हरियाणा अधिनियम संख्या 15)

{दि हरियाणा कामन परपज़िज लैन्ड इविकशन एण्ड रेन्ट रिकवरी ऐक्ट, 1985, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल के तिथि 25 फरवरी, 1986, के प्राधिकार के अधीन एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक गठ समझा जाएगा :— }

1	2	3	4
वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	विधान द्वारा निररित या अन्यथा प्रभावित
1985	15	हरियाणा सामान्य प्रयोजन भूमि बेदखली तथा किराया वसूली अधिनियम, 1985	—

पूर्वी पंजाब जोत (समेकन तथा खण्डकरण निवारण)  
अधिनियम, 1948, के अधीन सामान्य प्रयोजनों  
के लिए आरक्षित भूमि में से अनधिकृत  
अधिमोगियों की बेदखली के लिए  
उपबन्ध करने हेतु  
अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम हरियाणा सामान्य प्रयोजन भूमि बेदखली तथा किराया वसूली अधिनियम, 1985, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "सामान्य प्रयोजन भूमि" से अभिप्राय है, पूर्वी पंजाब जोत (समेकन तथा खण्डकरण निवारण) अधिनियम, 1948, की धारा 18 के अधीन किसी ग्राम के सामान्य प्रयोजनों के लिये आरक्षित भूमि जिसका प्रबन्ध तथा नियंत्रण पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 23-क के अधीन राज्य सरकार अथवा ग्राम पंचायत में निहित हो। परिभाषा।

3. उस समय लागू किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, हरियाणा लोक परिसर और भूमि (बेदखली तथा किराया वसूली) अधिनियम, 1972, के उपबन्ध सामान्य प्रयोजन भूमि को, जो उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये लोक परिसर समझी जाएगी, लागू होंगे। 1972 के हरियाणा अधिनियम 24 का सामान्य प्रयोजन भूमि को लागू होना।

1. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए, देखिए हरियाणा राजपत्र (असाधारण) दिनांक 26 सितम्बर, 1985, अंग्रेजी पृष्ठ संख्या 1612 तथा हिन्दी पृष्ठ संख्या 1613.